SHRI MANMOHAN SINGH: Sir, I had said earlier that we are as sincere as anybody else in seeing that nothing is done as hurt the country's exports. If any specific problem of lack of coordination between the Customs Department on the one hand and the Excise Department on the other is brought to my notice, I will look into it.

ऊर्जा के क्षेत्र में हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन

*102. **श्री रामजी लाल** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पिछले कई महीनों में ऊर्जा क्षेत्र के लिये अनेक समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा कितनी परियोजनायें निकट भविष्य में चालू हो जाएंगी और इनके परिणाम-स्वरूप कितनी अतिरिक्त बिजली तैयार हो सकेगी;

(ग) क्या इन समझौता-ज्ञापनों के जरिये ऊर्जा क्षेत्र में निवेश जारी है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या नीति है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. तथा ऊर्जा प्रबंध केन्द्र के बीच निजी विद्युत प्रवर्तकों के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ख) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [**देखिये** परिशिष्ट 173, अनुपत्र संख्या 25] निजी विद्युत परियोजनाओं का प्रचालन, इनके लिये सभी अपेक्षित स्वीकृतियां, वित्तीय समापन होने और परियोजनाओं का निर्माणकार्य पूरा हो जाने के पश्चात ही किया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं में से दभोल चरण-I (695 मे.वा.), इब घाटी ताप विद्युत केन्द्र (420 मे.वा.) और पागुथान सी सी जी टी (655 मे.वा.) के लिये सभी प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं और दभोल चरण-I ने वित्तीय समापन की स्थिति भी प्राप्त कर ली है।

(ग) और (घ) दिनांक 18-01-1995 के पत्र के जरिये भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह सूचित कर दिया है कि भावी विद्युत परियोजनायें प्रस्तुत किए जाने के लिये समझौता ज्ञापन की पद्धति के स्थान पर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिये। तथापि, विद्यमान समझौता ज्ञापनों के वित्तीय समापन हेतु समुचित समयावधि दी जायेगी।

श्री रामजी लाल : सभापति जी, मंत्री महोदय ने सभा पटल पर रखे विवरण में 121 एम०ओ०यू० साइन जाने का जिक्र किया है और कहा है कि—

"Mous have been signed between the State Government, State Electricity Boards, Powergrid Corporation of India Limited and Energy Management Centre with private power proponents."

मैं मंत्री महोदय को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि इस थोड़े ही समय में 121 एम०ओ०यू० साइन किये गये है जिसके संबंध में आंध्र प्रदेश से लेकर हरियाणा और सारा विवरण इस पत्र में दिया हुआ है। सभापति जी यह जो 121 एम० ओ०यू० साइन किये गये है जिनके जरिये 56,579 मेगावाट बिजली तैयार होगी, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट कब तक तैयार हो जायेंगे और इन सबसे बिजली का जनरेशन और प्रोडक्शन कब तक शुरू

होगा ? आपने प्रत्येक एम०ओ०यूज० का ब्यौरा दिया है, यह कब तक चालू हो जायेंगे ? अभी भारतवर्ष में जो बिजली की क्राइसिस है, तो क्या इन एम०ओ० यूज० से पावर सेक्टर में इनवेस्टमेंट और बिजली बढ़ेगी ? क्या सरकार ने पावर मिनिस्ट्री में कोई सेल बनाया है जोकि प्रत्येक एम०ओ०यूज० के टार्गेट को देखेगा ताकि वह जल्दी पूरा हो सके और क्या इन सभी एम०ओ०यूज० को साइन करते वक्त देश के हायडल, थर्मल व कोल सोर्स का ध्यान रखा गया है ?

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI RAMJI LAL: I am concluding, Sir.

क्या सरकार ने इस पालिसी को मंजूर करने के लिये देश के सभी मुख्य मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल : सर, जिन 121 प्रोजेक्ट्स में एम०ओ० यूज० साइन किये गये हैं, ये एम०ओ० यूज० साइन करने के बाद उसका नेसेसरी । क्लियरेंस भी होना चाहिये, फायनेंसियल क्लोजर के लिये भी उसको भेजना चाहिये और यह सब प्रोसीजर पूरा हो तभी उसका काम शुरू हो सकता है । तो यह जो 121 एम०ओ०यूज० साइन किये गये हैं, उनका जब ये प्रोसीजर पूरा होगा तभी उनका काम शुरू होगा और इस बारे में पालिसी तय करने के लिये हमारे पावर मिनिस्टर ने मुख्य मंत्रियों के साथ मशविरा भी किया था ।

MR. CHAIRMAN: Please don't read out all this. Will you ask question?

श्री रामजी लाल : सभापति जी, इसमें सरकार ने एम०ओ०यूज० में यह क्लैरीफाई नहीं किया कि प्रत्येक प्रोजेक्ट का केपेसिटी यूटिलाइजेशन हंड्रेड परसेंट होगा या नहीं होगा? मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 25-1-95 को इजरायल की कम्पनी से एक एम०ओ०यू०० साइन हुआ है । यह पहले 1987 में एन०टी०जै०पी०सी०को दिया गया था, लेकिन एन०टी०पी०सी० से क्लियरेंस नहीं मिली । दूसरे एनवायरनमेंट नं० 1 सी०ई०ए० अप्रूवल कोल लीकेज से ली हुई है । इसमें रेलवे लाने, ले जाने में फेसिलिटी देगी । क्योंकि एन.टी.पी.सी. के नाम यह कम्पनी के साथ काम 1987 से 1994 तक हुआ, अप्रैल, 1994 में, साल के शुरू में सरकार ने इजरायल कम्पनी के साथ साईन किये, जो एन.टी.पी.सी. की अप्रूवल थी, हमारी प्रार्थना है कि वह एच०एस०ई० बी० के नाम कर दिया जाये । इसे यमुना नगर थर्मल पावर कम्पनी के नाम सीधे ट्रांसफर किया जाये.. (**व्यवधान**) .. मान्यवर नहीं तो सालों साल इसमें लग जायेंगे और यह प्रोजेक्ट ऐसे का ऐसा रहेगा । ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN: Will you please put your question?

श्री रामजी लाल : एक मिनट, सर ।

I am coming to the question.

300 मेगावाट बिजली माननीय मंत्री जी ने हरियाणा को दी वरना हरियाणा में अंधेरा हो जाता और आज यहां बिजली नहीं होती । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको जल्दी क्लीयर किया जाय ताकि हरियाणा का यह एक प्रोजेक्ट क्लीयर हो जाये और जल्दी से वहां काम चालू हो जाये ।

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : मान्यवर, हरियाणा में यमुना नगर प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का एन.टी.पी.सी. को पहले दिया हुआ था, मगर दो साल पहले, डेढ़ साल पहले एन.टी.पी.सी. के पास इतने साधन नहीं थे कि वह इस प्रकल्प को पूरा कर सके । तो हरियाणा सरकार की सहमति से यह आइसेनबर्ग ग्रुप इजरायल के हैं, अमरीका के है, उनको दे दिया गया और इस प्रोजेक्ट में

पावर परचेज एग्रीमेंट में, मुझे ऐसा पता चला है कि, इसमें दस्तखत हो गये हैं। जल्दी से जल्दी यह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो, इसकी हम कोशिश करेंगे।

श्री रामजी लाल : सर, आपसे प्रार्थना है कि आइसेनबर्ग ग्रुप नाम का जल्दी से ऐलान किया जाये।. . (व्यवधान) . .

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Mr. Chairman, Sir, much publicity has been given in the Press to the State Governments signing MOUs with visiting foreign dignitaries who came to this country and meeting the Press and Chief Ministers and Ministers visiting foreign countries. Since 1992, nearly 121 MOUs have been signed. The answer says that only one project has been cleared technically and financially in three years. Many State Governments are complaining that projects are pending with the Central Government for years together. The State Governments will have to run about from one Department to the other Department and from pillar to post. If one project is cleared in three years, then, how many years would they take to clear the remaining projects? Power is the main centre of our progress. Both political power and the power of approval of signing MOUs is also concentrated in Delhi. How long will they take to clear the remaining projectss?

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल : सर, जहां एम०ओ०यू० साइन होते हैं तो दोनों पार्टी अपने इंटेंशन के बारे में समझौता करके एम०यू०ओ० साइन करते है। उसमें सब फार्मलिटीज रहती है और जो फार्मलिटीज करनी पड़ती हैं, उसमें टेक्नीकल क्लीयरेंस जरूरी है, इसकी कोस्ट एस्टीमेट भी चैक करना जरूरी है, उसका जो वाटर या कोल या जो मेटेरियल जरूरी है, उसके बारे में भी पूरी चैक करना जरूरी है। करीब 17 अलग-अलग क्लीयरेंस उसमें जरूरी होती हैं। कई बातों में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की क्लीयरेंस जरूरी होती है। यह सब प्रोसीजर करने में टाइम लगता है। अगर पूरी चेकिंग न हो तो बहुत सी गड़बड़ी रह जायेंगी और बाद में प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होगा। इस में पहले सब चेकिंग करना बहुत जरूरी है। तो उसमें टाइम हो जाता है और किसी एक प्रोजेक्ट के लिये इतना टाइम होगा, यह भी हम तय नहीं कर पायेंगे क्योंकि अलग-अलग प्रोजेक्ट का अलग-अलग सर्कमस्टांसेस में करना होता है, वहां की ज्योग्रफिकली कंडीशन भी अलग होती है तो इसलिये टाइम होता है। इसमें कोई बिन जरूरी दखल करके टाइम नहीं लगता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो इंफारमेशन या क्लीयरेंस के लिये चाहिए, वह पार्टी पूरी नहीं देती है। तो बार-बार उसकी इंक्वायरी भी करनी पड़ती है, यही वजह है कि यहां टाइम लग जाता है।

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister wants to add something.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, the situation is not as depressing as is sought to be made implicit in the question itself. Undoubtelly, there are 17 statutory and non-statutory clearance. But the time taken in India by private projects is the least in the world. I am making this statement with the highest responsibility. In the USA, it takes eight years: in Pakistan, it takes 10 yeahs: and in China, it takes much longer. All that I am submitting to you, Sir, is that putting up a power project in the private sector is not very easy. Apart from the 17 statutory and non-statutory clearance it is a very highly capital-intensive industry and the financial closure is not easy. We signed one counter-guarantee. It took them seven months after the counter-guarantee was signed. In two

cases, counter-guaranty have already been signed and in the rest; it is on the anvil. My friend, Mr. Bommai, will, perhaps, be pleased to know that by 1997, we expect to have 3135 magawatts of power generated by the private sector in as many as seven projects. By all standards, this will be a fairly expeditious implementation of our private power development. We, in our Ministry, do not want anyone to come and waste even one minute. Whatever are the problems of any private sector power developer, we attend to those problems expeditiously. But it is unavoidable; it is implicit; in the very implementation fo the scheme of private power development that it would take its own time. But once it gains momentum, their, perhaps, things would move fast.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Sir, my point is that within three years, only one project has been cleared. I am happy to know that in the Power Ministry things are flowing very fast.

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister has said that by 1997, you will get so many power projects.

SHRI SOMAPPA R. BOMMAI: Mr. Minister, I would like to know whether you will have a time-bound clearance. You reject it or accept it.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, the hon. Member is not aware to the legal procedure. It does not come to the Ministry. According to the statutory provision, according to the Electricity Act, every scheme above Rs. 100 crores has to be submitted to the Central Electricity Authority. It examines the scheme; it approves the scheme. Thereafter, it is for the developers to implement the project as fact as they can.

MR. CHAIRMAN: Shri Surjewala.

श्री नरेश यादव : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं . . . (**व्यवधान**) . . .

MR. CHAIRMAN: I have called Mr. Surjewala.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : चेयरमैन महोदय, मैं सबसे पहले श्री साल्वे जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि यमुना नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है, उसको लगाने के लिए भारत सरकार पूरी मदद करेगी। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा में बिजली की बहुत भारी कमी है, खास तौर से जब गेहूं की और धान की बुआई का समय आता है, साल्वे जी इस बात को भली-भांति जानते हैं कि हरियाणा सरकार रोज उनके दरवाजे पर बिजली मांगने के लिए खड़ी रहती है। पहले इनको यह शिकायत रहती थी कि हरियाणा बिजली बोर्ड पर बहुत सा रुपया पिछली बिजली खरीद का बकाया है, उसने वह नहीं दिया है लेकिन अब मैं इनके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने रुपया दे दिया है और करंट जो बिजली वे ले रहे हैं, उसकी भी अदायगी शायद वे करने लग रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यमुना नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो ओरिजनली 1000 मैगावाट का बनना था, 1000 से कम करके अब 700 मेगावाट पर आ गए हैं। 1982-83 के बीच में सारी क्लिअरेंस मिल चुकी थीं इसके सिवाय फाइनेंशियल टाइ-अप के और बाकी सारी क्लिअरेंस-कोल क्लिअरेंस, रेल लिंकेज और सी.ई.ए. ने, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने, फाइनेंस कमीशन ने, सब ने क्लिअर कर दिया था। यह इतना डिलेड प्रोजेक्ट है कि इससे बड़ा भारी नुकसान हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude, now.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इसमें कोई समय-सीमा निर्धारित कर सकेंगे, जिस निर्धारित समय में यमुना नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट का काम सरकार शुरू करवा सके और उसकी कंप्लीशन के लिए भी कोई समय बता सकेंगे? इसके साथ ही एक सवाल और जुड़ा है वह मैं पूछना चाहता

हूं। यह जो रीजनेबिल टरेशन इन्होंने...
(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: If you make your question short, then the answer will be quicker and others also can ask questions.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : क्या कोई समय निर्धारित कर सकेंगे कम्पलीशन आफ स्टार्ट का और यह जो इन्होंने रीजनेबिल टाईम दे रखा है–इन अचीविंग दि फाईनल क्लोजर आफ एम.ओ.यूज. में, यह रीजनेबिल टाईम का क्या मतलब है? कितने साल को यह रीजनेबल मानते हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं?

श्री एन० के० पी० साल्वे : सर, पूरे उत्तर भारत में बिजली की कमी रही है। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं राजस्थान में भी है, पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और यह तो इस वजह से है कि स्टेट्स ने भी अपनी बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया। हमसे जितना हो सका, हमारी जितनी बिजली है, हम तो दे ही रहे हैं। मगर फिर भी हरियाणा को यथासंभव हमने मदद की। अब आज यह एक खुशखबरी दे रहे हैं कि उन्होंने पैसा दे दिया है। अब मैं जाकर चैकअप करूंगा। अगर नहीं दिलवाया हो तो माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारे पैसे दिलवा दीजिए। रहा सवाल हरियाणा के यमुना नगर के प्लांट का। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है, एक सेकेंड की भी देरी नहीं है, अध्यक्ष जी, हमारी तरफ से। यह अब हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा गवर्नमेंट और आयसनवर ग्रुप के बीच में है। जितना जल्दी से जल्दी यह करना चाहें उतना जल्दी यह प्रोजेक्ट हो जाएगा।

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहूंगा, जो आपने उत्तर के भाग-सी और डी में कहा है कि एक पत्र के द्वारा :

The Government of India has informed all the State Governments that all future private power projects should come through the process of competitive bidding instead of the MOU route.

महोदय, निश्चित रूप से भारत सरकार का यह कदम सराहनीय है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कितने राज्यों ने सरकार के इन निर्देशों का पालन किया है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसने कि इस प्रकार डायरेक्टिव जारी होने के बाद कई एग्रीमेंट किए हैं। जैसे, चंदौसी पावर प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट, अलीगढ़ पावर प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट गजरौला पावर प्रोजेक्ट, कोसीकलां पावर प्रोजेक्ट। ऐसे कई प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट किए हैं। तो क्या भारत सरकार के निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पालन किया है या नहीं किया है? साथ ही यह भी जानना चाहूंगा–दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि गांवों के विद्युतीकरण यानी भारतवर्ष में आने वाले जितने गांव हैं जिनका अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उन गांवों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही औद्योगिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पावर जेनिरेशन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया है?

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश ने 13 प्रोजक्ट दिए हैं जो निर्धारित समय के अंदर ही आए हैं। इसके बाहर अगर कुछ किया हो तो वह यहां नहीं भेजा गया है। गांवों के विद्युतिकरण के बारे में हमारी सरकार प्रत्येक गांव को विद्युत देने का निर्देश जारी कर सकी है और जैसे-जैसे... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : यह उत्तर नहीं है हमारे प्रश्न का। मैं यह जानना चाहता हूं कि कम्पटीटिव बिडिंग के द्वारा आने की बात जो कही गई है भारत सरकार के द्वारा, उसका अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है अथवा नहीं कर रही है?

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल : इस तारीख के बाद यहां एक भी एम०ओ० यू० नहीं आया है। इसके मायने ही यही है कि सरकार पालन कर रही है।

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी, इसकी जांच कराने की

कृपा करेंगे कि वहां पर भारत सरकार के निदशों का पालन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है ?

श्री एन०के०पी० साल्वे : उत्तर में अगर आपने देखा हो तो अनेक्जर में हमने उन एम०ओ०यूज० का जिक्र किया है जो हमारे पास आए हैं। अनेक्जर में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से हमारे पास 13 प्रपोजल आए हैं। प्राइवेट सेक्टर में। उन 13 में तारीख दी है कि उन एम०ओ०यूज० की तारीख क्या है। इनकी तारीख 18 फरवरी के अंदर की तारीख है। इसके बाद अगर उन्होंने कोई एम०ओ०यू० साईन किया हो तो उसकी जानकारी हमें नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह : भारत सरकार का जो निर्देश है, वह 18–1–95 का निर्देश है और उसके बाद फरवरी में ये सब एग्रीमेंट हुए हैं।

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Thhere are ten power projects after the guidelines were issued by you.

श्री राजनाथ सिंह : उसकी जानकारी हम चाहिए।

SHRI PRAMOD MAHAJAN: We know that the guidelines are issued because you had lost interest in Dabhol when you went in for competitive bidding, but there are ten projects after you have gone in for competitive bidding.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, I had written much before, in 1993, that it should come to the competitive bidding. Imputing motives like this ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Why was this competitive bidding not applied to Dabhol?...(*Interruptions*)...

SHRII N. K. P. SALVE: Sir, this is the very unfair. If you want. let there be a debate on this.

...(*Interruptions*)...

Why is he imputing motives like this in the Question Hour?..(*Interruptions*)...We have been persistently asking... (*Interruptions*).

SHRI VIREN J. SHAH: You are assuming it ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no, no. Please sit down.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, we have been persistently wanting States to accept, adopt the bidding route. Now we have directed them that beyond a point we are not accepting the MOU route. Only a bidding route is to be there. There is a representation by the States that we should extend the date. That is under consideration. But the question of the hon. Member is that if they have signed any MOUs after the date, i.e. the 18th of February, 1995, that is the cut-off date.

SHRI P. UPENDRA: It is 18th January?

SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Only the letter was written on that date. ..(*Interruptions*)..

SHRI N. K. P. SALVE: No. no; the cut-off date is 18th February. I have the direction here which is sent by the Ministry. It is a letter addressed by Shri R. C. Meena, Adviser, in which it is being written that the Ministry of Power has taken a decision that the Central Electricity Authority will consider only those project proposals for which they have taken economic clearance and which have been selected through the process of comptitive bidding in future. In order to monitor the implementation of this decision, it is requested that the information about the MOUs signed between the promotors and the State Government up to 18th February, 1995 may kindly be furnished. So, 18th February is the cut-off date. Now, the information available to us from the State of Uttar Pradesh shows that they have signed 19 MOUs for 3,140 megawatts and all those are within the cut-off date so far as we know.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 103. Shri B. K. Hariprasad. Not present. ... (*Interruptions*).

*103. [*The Questioner (Shri B. K. Hariprasad)* was absent. *Ftr answer vide col... ... infra)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he has not said anything about the MOUs signed by the Andhra Pradesh Government. ... (*Interruptions*)...

AN HON. MEMBER: Sir, it is an important question... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: I have passed on to another question. Q. No. 104. ... (*Interruptions*)... Please sit down... (*Interruptions*), ... No, no; I have passed on to another question.

(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, there are 23 MOUs sent by the Andhra Pradesh Government. What are they going to do? .. (*Interrupions*). .. Sir, it is a very serious matter. Twenty three MOUs were signed by the Andhra Pradesh Government on the same date. I do not know what the Minister is going to do about them.

MR. CHAIRMAN: If you want to discuss it in another form, you give a notice for Calling Attenion or whatever it may be. It cannot be discussed in this manner (*Interruptions*)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, this side has been totally ignored.

MR. CHAIRMAN: Shri Ramdas Agarwal. Q. No. 104.

India's Economic Policy

104. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Indian Express dated 26th February, 1995 under the caption "economists warn Government against pushing India into global system" criticising every aspect of the country's economic policy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Indian Express published a news item captioned "Economics warn Government against pushing India into global system" on the 26th February, 1995. The news item relates to a statement issued by a group of economists, in which it is claimed that the stabilisation and adjustment programmes have led to a decline in the rate of economic growth associated with an increase in unemployment and worsening of poverty, and continuing inflation. It claims that the improvement in the balance of payments is illusory. It also criticises foreign investment proposals in power, petroleum and telecommunications, the manner of public sectors disinvestment, increases in procurement prices etc.

(c) The Government does not agree with the analysis under by the economists. The assessment of the Government to the performance of the economy is fully documented in the Economic Survey for 1994-95.

श्री रामदास अग्रवाल : सभापति जी, मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया। मैं ऐसा समझता था कि चार बड़े राज्यों में जनता ने इनकी जो अर्थ-नीति दोषपूर्ण रही, उसको ठुकरा दिया है। उसके बाद, ठोकर खाने के बाद तो कम से कम ये अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने का सोचेंगे। देश के कुछ प्रबुद्ध इकानामिस्ट्स ने, अर्थशास्त्रियों ने एक वक्तव्य के द्वारा देश में चल रही आर्थिक नीति के संबंध में कुछ संभावनायें और कुछ ऐसी परिस्थितियां जिनका उनको लगता है कि आ सकती है और देश को